भूमि अधिग्रहण अधिकारी, हैदराबाद शहरी

विकास प्राधिकरण, हैदराबाद, ए.पी.

बनाम

मोहम्मद अमरी खान और अन्य

30 सितम्बर, 1985

[पी.एन. भगवती, सी.जे., आर.एस. पाठक और अमरेरा नाथ सेन, जे.जे]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, धारा 4(1) और भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन और मान्यकरण) अधिनियम, 1983, धारा 3(1) और 2 भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना का आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन और सार्वजनिक सूचना स्थानीय है क्या दोनों चाहिए एक साथ या एक दूसरे के तुरंत बाद - संशोधित धारा 4(1) में समय अंतराल की सीमा को पूर्वव्यापी प्रभाव से 4 दिन कर दिया गया है - सार्वजनिक सूचना जारी करने में दो महीने से अधिक की देरी क्या अधिसूचना को अमान्य करती है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने धारा 4 उप-धारा (1) के तहत एक अधिसूचना जारी की। हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एचडीए) के उद्देश्य के लिए कुछ भूमि प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और इसे 4 अगस्त, 1977 को आंध्र प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना दी गई थी। इलाके में

सुविधाजनक स्थानों पर, लगभग 2 महीने की अवधि के बाद, 3 अक्टूबर, 1977 को 10.1.1979 को, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 6 के तहत एक और अधिसूचना जारी की, जिसमें एक भूमि को छोड़कर यह घोषणा की गई कि भूमि का शेष क्षेत्र के प्रयोजन हेतु आवश्यक था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 27 जुलाई 1981 को एक पुरस्कार दिया और अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचित क्षेत्र में शामिल भूमि पर कब्जा देने के लिए उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में उपरोक्त अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती दी। 3 दिसंबर, 1982 की पूर्ण न्यायपीठ के फैसले के बाद, हाई कोर्ट ने इस आधार पर रिट याचिका की अनुमति दी कि अधिसूचना के सार का स्थानीय प्रकाशन के तहत किया जाएगा। धारा 4 उप-धारा (1) उसी दिन नहीं बनाई गई थी जिस दिन अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और इसलिए, धारा 4 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना अमान्य था और धारा 4 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने के अधिकार क्षेत्र की नींव थी, धारा 6 के तहत अधिसूचना भी विफल रही।

दीपक पालवा बनाम उपराज्यपाल दिल्ली और अन्य [1984] 4 एससीसी 308 में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद माना कि उप-धारा 4 के (1) में कुछ भी नहीं है। जिसके

अनुसार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक सूचना एक साथ या एक दूसरे के तुरंत बाद होनी चाहिए, लेकिन राजपत्र में प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक सूचना के बीच बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। क्रिया की निरंतरता में विघ्न का द्योतक होगा। हालाँकि, दीपक पालवा के मामले में निर्णय से पहले, आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन और मान्यता) अधिनियम 1983 (संक्षेप में, संशोधन अधिनियम) 12 सितंबर, 1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 4 उप-धारा (1) संशोधन के बाद अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान किया गया कि कलेक्टर, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर, इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया (1) कि विधानमंडल इस धारणा पर आगे बढ़ा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ का फैसला इस विषय पर सही कानून का प्रतिनिधित्व करता है और यह उस धारणा पर था कि लैंडिंग अधिनियम अधिनियमित किया गया था। विधानमंडल द्वारा यदि, दीपक पालवा के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण समुद्र तट फैसले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उलट दिए जाने पर, विधायिका द्वारा की गई धारणा गलत निकली और यह पाया गया कि विधायिका कानून के गलत दृष्टिकोण पर आगे

बढ़ी। संशोधित अधिनियम को लागू करने में, संशोधन अधिनियम को अतिश्योक्तिपूर्ण माना जाना चाहिए न कि संशोधन अधिनियम को, लेकिन संशोधन अधिनियम से पहले प्रचलित सही कानून को लागू किया जाना चाहिए; और (11) कि विधायिका ने 12 सितंबर, 1975 के बाद किए गए अधिग्रहणों को वैध बनाने के उद्देश्य से संशोधन अधिनियम बनाया, जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की निचली पीठ के फैसले के कारण अमान्य घोषित किए जाने योग्य थे और यह कभी नहीं हो सकता था। विधायिका का इरादा अमान्य करने का, अधिग्रहण जो किए जाने पर वैध थे और इसलिए संशोधन अधिनियम की धारा 2 जिसने उप-धारा (1) में संशोधन पेश किया। धारा 4 को पूर्वव्यापी प्रभाव के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे संचालन में संभावित के रूप में समझा जाना चाहिए।

अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित किया (1) संशोधन अधिनियम द्वारा सेकंड में किया गया पूर्वव्यापी संशोधन। 4 उप-धारा (1) अधिनियम की धारा के तहत अधिसूचनाओं को पूरी तरह से अमान्य करता है। 4 उप. (1) और धारा 6 द्वारा निर्मित इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार और इन अधिसूचनाओं को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को उस आधार से भिन्न आधार पर कायम रखा जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय के पक्ष में है। कारण चाहे जो भी हो, विधानमंडल ने संशोधन अधिनियम बनाया है, संशोधन अधिनियम

क़ानून की किताब में है और 12 सितंबर, 1975 से प्रभावी है और इसे इसके शब्दों के स्वाभाविक अर्थ के अनुसार प्रभावी किया जाना चाहिए। संशोधन को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं हो सकता। उप-धारा (1) में धारा 4 पूर्वव्यापी प्रभाव, जो उप-धारा (3) धारा संशोधन अधिनियम का 1 स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि यह होगा। वास्तव में, धारा 4 की उप-धारा 1 के अधिदेश के बीच कोई असंगति नहीं है और दीपक पालवा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून संशोधित धारा 4 की उप-धारा (1) क्या है? का तात्पर्य विधायी रूप से समय अंतराल की सीमा निर्धारित करना है। जिसके परे यह पूर्व निर्धारित होना चाहिए कि कार्रवाई की निरंतरता में रुकावट है। [155 बी-सी; 159 एफ-जी; 160 सी-डी]

1. (11) उप में निर्धारित आवश्यकता धारा 4 उप-धारा (1) जैसा कि यह 12 सितंबर, 1975 से और उसके बाद था, स्पष्ट रूप से धारा 4 उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अधिसूचना पर लागू होगा। 12 सितंबर 1975 को या उसके बाद उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किया गया। यदि मामले में धारा के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है। 4 उपधारा (1) 12 सितंबर, 1975 को या उसके बाद ऐसी अधिसूचना के प्रावधानों की सार्वजनिक सूचना आधिकारिक राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर इलाके में नहीं दी जाती है, इससे ऐसी अधिसूचना अमान्य हो जाएगी। .

1983 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5839-42

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 1981 के नंबर 5538, 5363, 3644 और 5722 में दिनांक 2.3.1983 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए 1983 की सी.ए. संख्या 5839 में पी.पी. राव, टी.वी.एस.एन. चारी और सुश्री वी. ग्रोवर।

अपीलकर्ताओं के लिए 1983 की सी.ए. संख्या 5840-42 में टी.वी.एस.एन. चारी और सुश्री वी. ग्रोवर।

उत्तरदाताओं के लिए 1983 की सी.ए. संख्या 5839 में आर.पी. भट्ट, के. राजेंद्र चौधरी और के.एस. चौधरी।

प्रतिवादियों की ओर से 1983 सी.ए. संख्या 5840-42 में राजेंद्र चौधरी और के.एस. चौधरी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

भगवती, सी.जे.।

विशेष अनुमति द्वारा की गई इन अपीलों का शायद एक अलग भाग्य होता यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को आंध्र प्रदेश राज्य में लागू करने के लिए भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधित नहीं किया गया होता (इसके बाद संशोधन अधिनियम के रूप में संदर्भित) 12 सितंबर, 1975 से पूर्वव्यापी

प्रभाव के साथ। धारा 4 उप-धारा (1) में अंतिम अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी संशोधन। अधिनियम धारा 4 उप-धारा-(1) के तहत अधिसूचनाओं को पूरी तरह से अमान्य करता है और धारा 6 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी और इसलिए इन अधिसूचनाओं को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए। इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य कम हैं और संक्षेप में इस प्रकार बताए जा सकते हैं:

आंध्र प्रदेश सरकार ने धारा 4 उप-धारा-(1) के तहत एक अधिसूचना जारी की। जिसमें कहा गया है कि हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (इसके बाद हुडा के रूप में संदर्भित) के उद्देश्य के लिए कुल 35 एकड़ और 35 गुंठा क्षेत्र की आवश्यकता होने की संभावना है। अधिसूचना आंध्र प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। 4 अगस्त, 1977 को और अधिसूचना की सार्वजनिक सूचना लगभग 2 महीने की अवधि के बाद, 3 अक्टूबर, 1977 को इलाके में परिवर्तित स्थानों पर दी गई। इसके बाद विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी धारा 5-ए अधिनियम के तहत एक जांच की गई और जांच के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक गायत्री देवी सहकारी आवास सोसायटी से संबंधित 6 एकड़ 6 गुंठा के क्षेत्र को बाहर करने का निर्णय लिया गया और धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई। 10 जनवरी, 1979 को अधिनियम में घोषणा की गई कि भूमि का शेष क्षेत्रफल 29 एकड़ 29 गुंठन हुडा के उद्देश्य के लिए आवश्यक था। नोटिस धारा 9

के तहत फिर इन अपीलों में प्रतिवादियों को जारी किया गया जो धारा 6 के तहत अधिसूचित क्षेत्र में शामिल भूमि के विभिन्न पार्सल के मालिक हैं। और जांच करने के बाद, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 27 जुलाई, 1981 को एक पुरस्कार दिया और उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर अधिग्रहीत भूमि पर कब्ज़ा देने का आह्वान किया। इसके बाद उत्तरदाताओं ने धारा के तहत अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में रिट याचिका धारा 4 उप-धारा (1) दायर की और धारा 6 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी।

विवादित अधिसूचनाओं की वैधता के खिलाफ उत्तरदाताओं की ओर से कई तर्क उठाए गए थे, एक को छोड़कर, सभी को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। एक विवाद जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन मिला वह स्थानीय था। धारा 4 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना का सार्वजनिक प्रकाशन उसी दिन नहीं बनाया गया था जिस दिन अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, बल्कि इसे लगभग 2 महीने बाद जारी किया गया था और धारा 4 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। इसलिए अमान्य था और धारा के तहत अधिसूचना धारा 4 उप-धारा (1) अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने के क्षेत्राधिकार का आधार होने के नाते, धारा 6 के तहत अधिसूचना भी असफल होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5722/1981 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं में 3

दिसंबर, 1982 को दिए गए पूर्ण न्यायपीठ के फैसले के बाद इस तर्क को स्वीकार कर लिया और धारा 4 उप-धारा (1) और धारा 6 के तहत अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने इस न्यायालय से प्राप्त विशेष अनुमति के साथ वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी।

इन अपीलों में मुख्य प्रश्न यह उठता प्रतीत होता है कि क्या उच्च न्यायालय की सही व्याख्या पर यह विचार करने में सही था। धारा 4 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना उसी दिन उस इलाके में दी जानी चाहिए जिस दिन अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होती है और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या इसका कोई अमान्य परिणाम होगा। जिस समय उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में अपना फैसला सुनाया, उस समय इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बाद, यह प्रश्न इसकी एक पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। विशेष अनुमति याचिकाओं में अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ निर्देश दिया, जिसने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले में लिए गए फैसले से अलग दृष्टिकोण अपनाया था। इस न्यायालय ने दीपक पालवा बनाम उपराज्यपाल दिल्ली और अन्य में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में यह व्यवस्था दी। [1984] 4 एससीसी 308, हालांकि आधिकारिक

राजपत्र में प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक सूचना धारा 4 उप-धारा (1) के तहत उठाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण कदम हैं। जिसके बिना धारा 4 उप-धारा (2) के तहत विचार किए गए कदम नहीं उठाए जा सकते, धारा 4 के उप-धारा (1) में कुछ भी नहीं है। जिसके लिए आवश्यक है कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक सूचना एक साथ या एक दूसरे के तुरंत बाद होनी चाहिए। इस न्यायालय ने बताया कि धारा 4 की उप-धारा (1) क्या है में आवश्यक है कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक सूचना समसामयिक होनी चाहिए लेकिन समसामयिकता में समकालिकता या तात्कालिकता शामिल नहीं है। सरकारी राजपत्र के प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक सूचना के बीच समय का अंतराल होना तय है, लेकिन जरूरी यह है कि उन्हें इतने लंबे अंतराल से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि कार्रवाई की निरंतरता गहरी अन्तराल से टूटती हुई दिखाई दे। "यदि राजपत्र में प्रकाशन है," इस न्यायालय ने कहा, "और यदि इलाके में सार्वजनिक सूचना है तो धारा-4 की उप-धारा-(1) की आवश्यकताओं को संतुष्ट माना जाना चाहिए, जब तक कि दोनों को अलग नहीं किया जाता है समय के इतने बड़े अंतराल से एक-दूसरे के बीच अंतर हो सकता है, जिससे अधिग्रहण की कार्यवाही में प्रथम दृष्टया प्रामाणिकता की कमी का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यदि अधिसूचना और सार्वजनिक सूचना को समय के इतने बड़े अंतर से अलग किया जाता है, तो यह आवश्यक हो सकता है यह पता लगाने के लिए आगे की जांच

करना कि क्या देरी का कोई कारण है और क्या देरी के कारण किसी के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है।" वर्तमान अपीलों में लगाए गए निर्णय को दीपक पालवा के मामले (सुप्रा) में इस निर्णय द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 6 के तहत अधिसूचनाएँ को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के उप-विषय की सार्वजनिक सूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के दिन ही नहीं दिया गया था। हमें दीपक पालवा के मामले (सुप्रा) में निर्णय में निहित टिप्पणियों के आलोक में विचार करना होगा कि क्या आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक सूचना के बीच इतना बड़ा अंतर था कि निरंतरता कार्रवाई टूटी हुई प्रतीत होगी और इससे इस प्रश्न की जांच करना आवश्यक हो जाएगा कि क्या देरी का कोई उचित कारण था और क्या देरी के कारण उत्तरदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। लेकिन दीपक पालवा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले, आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने संशोधन अधिनियम बनाया जो 23 जून, 1983 से लागू हुआ और यह संशोधन अधिनियम है जो इसे हमारे लिए अनावश्यक बना देता है। इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या दीपक पालवा के मामले (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात के आवेदन पर धारा के तहत आक्षेपित अधिसूचना है। धारा 4 उप-धारा (1) कायम रखा जा सकता है या इसे अमान्य करार दिया जा सकता है।

अब हम संशोधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। डब्ल्यू.पी. में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए आंध्र प्रदेश विधानमंडल द्वारा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। 1981 की संख्या 5722 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाएं जहां अन्य बातों के अलावा यह माना गया था कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक सूचना एक ही दिन होनी चाहिए अन्यथा धारा के तहत अधिसूचना धारा 4 उप-धारा (1) अमान्य होगा इसलिए संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव और एनईसी की उपधारा-(3) दिया गया। धारा 1 में स्पष्ट रूप से अधिनियमित किया कि संशोधन अधिनियम 12 सितंबर, 1975 को लागू हुआ माना जाएगा। इसलिए, संशोधन अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान को एक निश्चित तिथि से प्रभावी माना जाना चाहिए अर्थात् 12 सितंबर, 1975 संशोधन अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अपने आवेदन में "कलेक्टर कारण बनेगा" शब्दों के लिए, "कलेक्टर, चालीस दिनों के भीतर किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, कारण", प्रतिस्थापित किया जाएगा। धारा 4 उप-धारा (1) का आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अपने आवेदन में इसलिए 12 सितंबर, 1975 से इस प्रकार पढ़ें:

"जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या इसकी आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की एक अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और कलेक्टर, तिथि से चालीस दिनों के भीतर ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में, ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर दी जाए"।

इसलिए क्या धारा 4 की उप-धारा (1) जैसा कि यह 12 सितंबर, 1975 से और उसके बाद था, बशर्ते कि उस धारा के तहत अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और अधिसूचना के सार की "सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर इलाके में दी जाएगी एक अधिसूचना।" यह आवश्यकता स्पष्ट रूप से 12 सितंबर, 1975 को या उसके बाद उपयुक्त सरकार द्वारा जारी धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अधिसूचना पर लागू होगी। यदि धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के मामले में उप-धारा (1) 12 सितंबर, 1975 को या उसके बाद, ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना आधिकारिक गैरेट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर इलाके में नहीं दी जाती है, यह एक परिचय देगा, घातक दुर्बलता कई अधिसूचनाओं को

अमान्य कर रही है। यहां वर्तमान मामले में, धारा 4 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना 4 अगस्त, 1977 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, लेकिन ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना इलाके में दी गई थी 3 अक्टूबर 1977 तक देर हो चुकी है। आधिकारिक राजपत्र में प्रत्येक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के चालीस दिन से अधिक समय बाद। इसलिए धारा 4 की उपधारा-(1) में अधिनियमित शासनादेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन था क्योंकि यह 12 सितंबर, 1975 के बाद से कायम है और धारा 4 उप-धारा-(1) के तहत अधिसूचना को अमान्य घोषित किया जा सकता था, हालाँकि यह उस आधार से भिन्न था जिसे उच्च न्यायालय ने समर्थन दिया था।

हालाँकि, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील धारा 4 की उप-धारा (1) का विरोध करके उस के पूर्वव्यापी संशोधन के परिणाम से बचने के लिए एक साहसी लेकिन निरर्थक प्रयास का पक्ष लेते हैं। अंतिम अधिनियम के 2 जिसने उप-धारा में संशोधन पेश किया। धारा 4 उप-धारा (1) का इसे पूर्वव्यापी प्रभाव के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे संचालन में संभावित के रूप में समझा जाना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि विधानमंडल ने 12 सितंबर , 1975 के बाद किए गए अधिग्रहणों को मान्य करने के उद्देश्य से संशोधन अधिनियम बनाया था, जो कि डब्ल्यू.पी. में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ

निर्णय के कारण अमान्य घोषित किए जा सकते थे। 1981 की संख्या 5722 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाएं और विधानमंडल का इरादा उन अधिग्रहणों को अमान्य करने का कभी नहीं हो सकता है जो किए जाने पर वैध थे। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विधायिका इस धारणा पर आगे बढ़ी कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ का फैसला इस विषय पर सही कानून का प्रतिनिधित्व करता है और यह इस धारणा पर था कि संशोधन अधिनियम विधायिका द्वारा अधिनियमित किया गया था। यदि, दीपक पालवा के मामले (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण समुद्र तट निर्णय को इस न्यायालय द्वारा उलट दिया गया तो विधानमंडल द्वारा की गई धारणा गलत निकली और यह पाया गया कि विधानमंडल गलत दृष्टिकोण पर आगे बढ़ा। संशोधन अधिनियम को लागू करने में कानून विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम को अनावश्यक माना जाना चाहिए और संशोधन अधिनियम नहीं, बल्कि सही कानून लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह संशोधन अधिनियम से पहले प्रचलित था। अपीलकर्ता की ओर से दिया गया यह तर्क पूरी तरह से फर्जी है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। यह निराशा का तर्क है और इसे खारिज करने के लिए ही कहा जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना असंभव है कि चूंकि संशोधन अधिनियम कानून के गलत दृष्टिकोण पर आगे बढ़ा है, इसलिए इसे अनावश्यक माना जाना चाहिए और सभी प्रभावों से वंचित किया जाना चाहिए। जो भी कारण हो जिसके लिए

विधायिका ने संशोधन अधिनियम लागू किया और यहां इसमें कोई संदेह नहीं है कि कारण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के फैसले के प्रभाव को शून्य करना था, संशोधन अधिनियम क़ानून की किताब पर है और प्रभाव से लागू है 12 सितंबर, 1975 से और इसे इसके शब्दों के स्पष्ट प्राकृतिक अर्थ के अनुसार प्रभाव दिया जाना चाहिए। धारा 1 की उप-धारा (3) का संशोधन अधिनियम स्पष्ट शब्दों में प्रावधान करता है, किसी भी अस्पष्टता या संदेह के प्रति संवेदनशील नहीं कि यह 12 सितंबर, 1975 से लागू होगा। यह धारा के संबंध में कोई अपवाद नहीं बनाता है। संशोधन अधिनियम के 2 और उस धारा 1 को भी, उप-धारा (3) में निहित स्पष्ट और स्पष्ट आदेश के अनुसार होना चाहिए। 12 सितंबर, 1975 को प्रभावी हुआ माना जाएगा। यह सच है कि यदि, धारा 4 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के मामले में। 12 सितंबर 1975 के बाद आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख और तारीख के बीच चालीस दिनों से अधिक का अंतर है। जब इलाके में इसके सार की सार्वजनिक सूचना दी गई, तो धारा 4 की उप-धारा (1) में 12 सितंबर , 1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित होने पर ऐसी अधिसूचना अमान्य हो जाएगी। लेकिन यह धारा 4 की उपधारा-(1) में संशोधन से इनकार करने का कोई आधार नहीं हो सकता। 4 पूर्वव्यापी प्रभाव, जो धारा 1 की उप-धारा (3) है संशोधन अधिनियम का धारा 4 की उप-धारा 1 स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि यह होगा। वास्तव में हमारे विचार से उप-धारा के

अधिदेश के बीच कोई असंगतता नहीं है। धारा 4 उप-धारा (1) दीपक पाला के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून। इस न्यायालय ने दीपक पालवा मामले में कहा कि राजपत्र में प्रकाशन और इलाके में सार्वजनिक सूचना के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह कार्रवाई की निरंतरता में रुकावट का संकेत होगा। संशोधित उपधारा क्या है? धारा 4 की उप-धारा (1) का तात्पर्य विधायिका द्वारा समय अंतराल की सीमा निर्धारित करना है जिसके परे यह माना जाना चाहिए कि कार्रवाई की निरंतरता में रुकावट है। इसलिए हमें अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के उस तर्क को अस्वीकार करना चाहिए जो धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतिम अधिनियम को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए ताकि उस अधिनियम की धारा 2 को इसके संचालन से बाहर रखा जा सके।

उन्होंने तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया, हालांकि उच्च न्यायालय में अपील की गई अपील से भिन्न आधार पर। प्रत्येक पक्ष अपनी पूरी लागत स्वयं वहन और भुगतान करेगा।

एम.एल.ए याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।